Scientific Innovation Magazine
ISSN : 2584-1157

किसानों के लिए सरकारी योजना 2024

श्रीमती किरण[1], मुनेश्वर प्रसाद मंडल[2],
[1]सहायक प्राध्यापक एवं वैज्ञानिक, जैव रसायन विभाग, आधार विज्ञान और मानविकी महाविद्यालय,
डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, बिहार
[2]सहायक प्राध्यापक सह कनीय वैज्ञानिक, पादप कार्यकी एवं जीव रसायन विभाग,
बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर बिहार

भारत की लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। इसके अलावा कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सरकार समय–समय पर कृषि कार्य की असुविधाओं को दूर करने के लिए योजनाएं लाती है और इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को अपनी समस्याओं का समाधान करने की सुविधा मिलती है। सरकारी कामकाज का मकसद किसानों के हित में खेत से लेकर घर तक व्यवस्था करना है। आज हम आपको किसानों के लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। अग्रीरूरल यूनियन और बैंक, कृषि/लघुउद्योग/तृतीय क्षेत्र जरूरतो के लिए उत्पादों और सेवाओं के लिए पूर्ण अनुकूलता उपलब्ध कराता है।

भारत की लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है। इसके साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था को सुद्यढ़ बनाने में भी कृषि का अहम योगदान है। देश की अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत करनें के लिए सरकार कृषि कार्यों में आनेवाली असुविधाओं को दूर करनें के लिए समय–समय पर योजनाये संचालित करती रहती है, ताकि किसान इन योजनाओं के माध्यम से अपनी समस्याओं का निराकरण कर सके। सरकार द्वारा किसानों के हित में संचालित योजनाओं में खेत से लेकर घर तक की व्यवस्था तक का उद्येश्य निहित है। आज हम आपको यहॉ आपको किसानों कि लिए सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारें में जानकारी देने जा रहे है।

सरकार द्वारा सरकारी योजनायें शुरू कारनें का उद्येश्य

सरकार द्वारा शुरू की जानें वाली यैोजनायें सामान्यः भारत में रहनें वाले सभी किसानों के लिए चलाई जाती है। सभी किसान भाईयों के आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती है, यहॉ तक कि

उनके लिए अपनें परिवार को भरण–पोषण करना तक कठिन हो जाता है। इस प्रकार की समस्यो को देखते हुए सरकार नें योजनाओं का संचालन करना शुरू किया, ताकि किसान भाई इन योजनाओं के माध्यम से अच्छी तरह से खेती कर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सके और अपने आर्थिक स्थिति में भी सूधार कर सके। किसानों के लिए सरकारी योजनाओं की सरकार द्वारा समय–समय पर विभिन्न प्रकार की योजनायें शुरू की जाती है, इनमें से कुछ मुख्य योजनायें और उनका विवरण इस प्रकार है।

1. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में प्रधानमंत्री किसान सम्ममन निधि एक योजना है। इस योजना की शुरूआत वर्ष 2018 के रबी सीजन में की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत किसान को 6000 रूप्य प्रति वर्ष तीन किस्तो में प्राप्त होते है और यह सहायता राशि सीधे अनके बैंक खाते में आती है। प्रत्येक चार माह के पश्र्चात कृषिक को 2000 रूपए की सहायता राशि प्राप्त होती है। आप को बता दे, कि इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 8 किश्तें जारी की जा चुकी है और अब किसानों 9वीं किश्त जल्द ही मिलने की संभावना है। इस स्कीम के माध्यम से किसानों को आर्थिक स्थिति सुधारनें में काफी सहायता मिती है। आपको बता दें, कि प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी योजना है। आपको बता दे की 15वीं किस्त के 2000रू0, 15 नवंबर 2023 को किसानों के बैंक में जमा किए गए थें और जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रत्येक 4 महीने में किसानों को योजना के तहत अगली किस्त प्राप्त होती है तो संभावना है कि पी एम किसानयोजना की 16वीं किस्त फरवरी 2024 के अंत तक या मार्च के मध्य तक किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर

2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

यह महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 18 फरवरी, 2016 को शुरू की गयी थी। अक्सर किसानों को तैयार फसल आंधी, ओलावृष्टी और तेज बारिस जैसी प्रॉकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हो जाती है। ऐसे में किसानों के सामनें अपना जीवन निर्वाह करनें की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण किसान आत्मजत्या भी कर लेते है। इस प्रकार की समस्याओं को देखतें हुए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शरूआत की गयी है। इस योजना के तहत रबी, फसलों को भी शामिल किया गया है। आपको बता दें, कि किसान को

खरीफ फसलों के लिए 2 प्रतिशत और रबी फसलों कि लिए 1.5 प्रतिशत का प्रीमियम भुगतान करना होता है।

3. किसान क्रेडिट कार्ड योजना

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की शुरूआत भारत सरकार द्वारा वर्ष 1998 में की गयी थी। किसानों को इस कार्ड की सहायता से प्र्याप्त ऋण (लोन) बहुत ही आसानी से मिल जाता है। जिस से किसान कृषि से सम्बंधित खाद–बीज, कीटनाशक आदि सामग्री खरीद सकते है। सबसे खास बात यह है, कि इस कार्ड से 5 वर्षों में 3 लाख तक का लोन ले सकते है। यदि किसान इस कार्ड पर लिए गये लोन को 1 वर्ष के अन्दर ही वापस कर देते है, तो उन्हें ब्याजदर में 3 प्रतिशत की छूट मिलती है। इसके अलावा यदि किसानों को अचानक धन की आवश्यकता होनें पर भी वह इस योजना के माध्यम से धन की प्राप्ति तत्काल रू‍प से कर सकते है।

4. प्रधनमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

केंद्र की मोदी सरकार नें नौकरी पेशा करनों वाले लोग की तरह किसानों के लिए पेंशन योजना की सौगात दी है। इस स्कीम के अंतर्गत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी करनें के पश्र्चात नयूनतम 3000 रूपए पेंशन दी जाती है। योजना का लाभ प्राप्त कारनें के लिए किसानों को 55 रूप्ए से लेकर 200 रूपये तक प्रति माह 60 वर्ष की आयु तक जमा करना होता है। जैसे ही किसान अपनी 60 वर्ष की आयु पूरी करता है, उन्हें पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। इस योजना की सबसे खास बात यह है, ि कइस स्कीम में जितना योगदान किसान का होता है, उतना ही योगदान करकार करती है। यदि किसी कारणवश किसान की मृत्यु हो जाती है, तो किसान की पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रू‍प में 50 प्रतिशत पेंशन प्राप्त होती है।

5. स्माम किसान योजना

आधुनिकता के इस दौर में देश में ऐसे बहुत से किसान है, जो कृषि कार्यों में आज भी पुरानें यंत्रो का उपयाग करते है। धन के अीाव में वह नए यन्त्र खरीदनें में असमर्थ होते है। किसानों की इस समस्या को देखतें हुए केंद्र सरकार द्वारा स्माम किसान योजना की शुरूआत की गयी है। इस स्कीम के माध्यम से किसान खेती करने वाले उपकरणों को आसानी से खरीद सकते है। सबसे खास बात यह है, कि उपकरणों की खरीद पर उन्हे छूट भी प्रदान की जाती है। सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करनें का मुख्य उद्येश्य किसानों को खेती करनें में किसी प्रकार की

समस्या न हो और वह बेतहर फसल का उत्पादन कर अपनें जीवन स्तर को सुधार सके।

6. पीएम कुसुम योजना

भारत के ग्रामीण क्षेत्रो में बिजली की समस्या अभी भी गंभीर बनी हुई है। जब किसानों के खेत को पानी की आवश्यकता होती है, तो उन्हें समय से बिजली नही मि पाती है। पानी के अभाव में उनकी फसलें प्रभावित हो जाती है। किसान भाइयों का निर्बाध बिजली उपलब्ध करानें के उद्येश्य से सरकार की तरफ से पीएम कुसुम योजना चलाई जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत किसानों को सालर पैनल सब्सिडी पर मिलते है, जिससे वह बिजली का उत्पारन कर अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका प्रयोग करनें के बाद बाकी को बेचकार अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते है।

7. डेयरी उद्यमिता विका स योजना (डीईडीएस)

किसानों की आय को बढ़ानें के उद्येश्य से डेयरी उद्यमिता विकास योजना (डीईडीएस) का संचालन केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। हमारे देश के लगभग किसान पशुपालन आवश्य करतें है। सरकार का मानना है, कि यदि यी कार्य एक बड़े पैमाने पर किया जाए, तो अच्छी मात्रा में दुग्ध उत्पादन किया जा सकता है और किसान भाई उपनी आय बढ़ा सकते है। इस योजना का लाभ लेकर किसान या पशुपालक नई डेयरी की स्थापना कर सकते है। यदि वह पहले से डेयरी चला रहे है, तो उसे आगे बढ़ा सकतें हैं। इस योजना के माध्यम से किसान को अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है, इसके साथ ही किसान भाई प्रशिक्षण भी ले सकते है।

8. पशुधन बीमा योजना

इस योजना की शुरू आत मुख्य रूप दो उद्येश्यों से की गयी है। किसानों या पशुपालकों को पशुओं की अचानक मृत्यु हो जानें पर उन्हें आर्थिक क्षति काफी होती है। इस प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्शुणन बीमा योजना चलायी जा रही है। योजना के अंतर्गत दुधारू मवेशियों और भैंसों का बीमा उनके अधिकतम बर्वतान बाजार मुल्य पर किया जाता है। बीमा का प्रीमियम 50 प्रतिशत तक अनुदानित होता है। अनुदान की पूरी लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है। अनुदान का लाभ अधिकनम 2 प्शु प्रति लाभार्थी को बिधकतम तीन वर्ष की एक पॉलिसी के लिए मिलता है। इस के साि ही इस स्कीम के अंतर्गत यदि कोई किसान अपनें पशुओं की बिक्री कर देता है, और बीमा पॉलिसी की अवधि समाप्त होती बीमा पॉलिसी

की शेष अवधि का लाभ नये स्वमी को हस्तांतरित किया जायगा।

9. मृदा स्वास्थ जिसके कार्ड योजना

किसानों के द्वारा अपनें खेतों में उत्पादन बढ़ाने को लेकर असंतुलित उर्वरक का उपयोग कर रहे है। लिसके कारण मिट्टी उत्पादकता निरंतर कम होती जा रही है, इसके साथ ही फसलों में विभिन्न प्रकार के नए–नए रोग लग रहे है। खेत की उत्पादकता बढ़ानें की जगह निरंतर कम होती चली जा रही है। जबकि दूसरी तरफ अधिक अर्वरक तथा रोग के लिए कीटनाशक उपयोग करने से कृषि खर्च भी बढ़ रहा है। इस प्रकार की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना संचालित की जा रही है। जिसमें किसानों की मिट्टि की जॉच वह भी निशुल्क की जाती है। खेत की मिट्टी की जॉच के दौरान यह ज्ञात हो जाता है, कि किसान के खेत में किस चीज की कमी है।

10. राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन योजना

ळमारे देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसें में सभी को भोजन सुनिक्षित कराने के लिए केंद्र सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खाध सुरक्षा मिशन योजना की शुरूआत की है। इस योजना का मुख्य उद्येश्य गेहूँ, चावल व दलहन की अत्पादकता में वृद्धि करना है, ताकि देश में खद्य सुरक्षा की स्थिति को सुनिश्चित किया जा सके। आप को बता दें, कि इस योजना के अंतर्गत चावल राष्ट्रीय खध सुरक्षा मिशन, गेंहू राष्ट्रीय खाध सुरक्षा मिशन तथा दलहन राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन को शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत चावल के लिए 14 राज्य, गेंहू के लिए 9 राज्य तथा दलहन के लिए 16 राज्यों को शामिल किया गया है।

11. मृदा हेल्थ कार्ड योजना

खेत में फसलों को बोनें के बाद फसलों की सेहत से सूबंधित जानकारी होना भी एक अहम बिंदु है। जिस प्रकार मनुष्य के कुछ भी खानें–पीनें पर उसका सीधा प्रीाव उन के स्वास्थ्य पर पड़ता है। ठीक उसी पगकार फसलों को दिए गये खाद, पारी आदि का फसल पर कया प्रीभव पड़ रहा है, इसकी जानकारी के लिए सरकार द्वारा स्वाल हेल्थ कार्ड योजना की शुरूआत की गयी हैं फसलों को कब और कितनी मात्रा में क्या चीज देनी है, इसकी सटीक जानकारी होनें पर स्वाभाविक रू‍प से उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे उन्हें अच्छी आय प्राप्त होगी। आपको बता दें, कि वर्ष 2015 से 2017 के बीच 10.73 करोड़ स्वायल हेल्थ कार्ड बनाए गए जबकि यह

आंकड़ा 2017 से 2019 के बीच 10.69 रहा है।

12. जैविक खेती योजना

वर्तमान समय में उत्पादकता बढानें कि लिए किसानों द्वारा रासायनिक खद का इस्तेमान अधिक किया जा रहा है। जिससे उत्पन्न अनाज, सब्जियों का खाकर लोग बीमार पड़ जाते हैं। इस समस्या को देखते हुए करकार द्वारा जैतिक खेती योजना को बढ़ावा देने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जैतिक खेती के अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरूआत की गई, जिसके तहत किसानों का बताया गया कि प्राकृतिक रूप से किस प्रकार कृषि की जाए और उस वक्त अनाज साग सब्जी का उत्पादन किया जाए। यहाँ तक कि जैविक खेती करनें वाले किसानों को सरकार की तरफ से पुरस्कृत भी किया जाता है। कृषि मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस समय देश भर में 27.10 लाख हेक्टेयर जमीन पर जैविक खेती की जा रही है।